



भारत का विद्युत वार्ता The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 1968/माघ 17, 1889

No 21] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 1968/MAGHA 17, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास चंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1968

विषयः—एक पुनर्वास बोड की स्थापना

संख्या 3(5)/67-श्र.र० ए ब०-V:—1916 से लेकर आज तक इग जग को पाकिस्तान से भारी संख्या में आने वाले अल्प-संख्यको का वाने के कार्य का भासना करना पड़ रहा है। परिवहन पाकिस्तान से आये अधिकाश विम्बापित व्यक्तियों के भूमि पर, तथा छाटेम टे दाग ग्राम व्यापार में वाया जा चुका है किन्तु जहा तक पूर्वी-पाकिस्तान से आने वाले विम्बापित व्यक्तियों नथा। इस गों में लौटने वाले भारतीयों की महायता तथा पुनर्वास का वस्त्रावर् यह अभी तह भारत 1968 वर्ष के विवरकारों के लिये एक मुख्य ममम्या और जिम्मेदारी बना रही है। युना त्रान ह 1968 वर्ष के विवरकारों ने किंवदन्ति व्यक्तियों ग्राम विदेशों ने ता 1968 वर्ष के युना श्रीर उद्देश्य देने के विवरकारों के लिये भारतीयों को वासाने के लिये त्रिवीय प्र । । भविष्य में केवल उद्याग तथा उपर्युक्ति

कार्यक्रम, विशेषकर एकीकृत क्षेत्र की विकास योजनाओं पर ही निर्भर होगा । उद्योग में विशेषकर प्रावेशिक विकास कार्यक्रम होंगे ("विशेष क्षेत्र") जिनमें दण्डकारण्य, अन्यमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चान्दा जिला (महाराष्ट्र) शास्त्र हैं ।

2. सगभग दस लाख से अधिक व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन तथा एकीकरण की चली आ रही आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने एक पुनर्वास-बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है । इस बोर्ड में राष्ट्रीय नेता और उद्योगपति होंगे जो सरकार को योजना तथा श्रौद्धोगिक और उससे सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार करने में सहाय होंगे ।

बोर्ड के विचारणीय विषय निम्न होंगे :—

- (1) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों और बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों से लौटने वाले भारतीयों को उद्योगों तथा अन्य गैर-कृषि कार्यक्रमों के प्रत्यर्गत पुनर्वास सम्बन्धी कार्य-नीतियों तथा उपायों के बारे में सलाह देना;
- (2) निम्नलिखित के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की मुख्य कठिनाहयों तथा समस्याओं के सम्बन्ध में गहन अध्ययन:—
 - (क) विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटने वालों को उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण तथा अन्य गैर-कृषि कार्यक्रमों में पुनर्व्यवस्थापन; और
 - (ख) दण्डकारण्य प्रायोजना क्षेत्र का श्रौद्धोगिक विकास तथा अन्य क्षेत्र जिन्हे "विशेष क्षेत्र" घोषित किया जा चुका है ।
- (3) निगम के उद्देश्यों तथा सक्षयों को ध्यान में रखते हुये पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा आस्तीन की गई योजनाओंके कार्य तथा प्रगति का निश्चय करना;
- (4) निम्नके बारे में योजना तैयार करने तथा उसे कार्य रूप देने के लिये सरकार की सहायता करना :—
 - (क) पुनर्वास उद्योग—निगम को आर्थिक वृद्धि से सुदृढ़ बनानेके लिये आवश्यक उपाय;
 - (ख) पुनर्वास उद्योग निगम, राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थानों और गैर-सरकारी श्रौद्धोगिक तथा वाणिज्य उद्योगों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटने वालों के लिये उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण और गैर-कृषि कार्यक्रमों के प्रत्यर्गत बनाने के लिये भावी कार्यक्रम और योजनाओं की रूप-रेखा निश्चित करना;
 - (ग) विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटने वालों को श्रिंखला संस्था में रोजगार पर लगाने के लिये उद्योग तथा दस्तकारी को प्रोत्साहन तथा सुविधाएं देने के सम्बन्ध में व्यापक कार्य नीति;
 - (घ) दण्डकारण्य तथा "विशेष क्षेत्र" [अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और चान्दा जिला (महाराष्ट्र)] में श्रौद्धोगिक विकास की गति बढ़ाने के लिये आवश्यक उपाय ।

4. बोर्ड का गठन निम्न प्रकार होगा :—

प्रमाण

1. श्री मनुभाई शाह ।

सदस्य

2. श्री आर० बैंकटारमन, सदस्य योजना प्रायोग ।
3. श्री ए० के० सेन, इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-निदेशक ।
4. श्री के० सी० मैत्रा, “गैस्ट, कीन विलियमस लिमिटेड”, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक ।
5. श्री ए० एम० एम० प्रसनान्नलम, “ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, भारत”,—मद्रास ।
6. श्री डॉ० सी० कोठारी, उद्योगपति, मद्रास ।
7. श्री ई० डकास्टा, भारतीय लोकमत सम्पादक, नई दिल्ली के प्रबन्ध निदेशक ।
8. औद्योगिक विकास तथा कम्पनी भागों के मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का एक प्रतिनिधि ।
9. वित्त मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि ।

सदस्य-सचिव

10. श्री श्री० धी० सूद, संयुक्त मंत्रिव, पुनर्वासि विभाग ।

5. बोर्ड को और सदस्य बनाने का अधिकार होगा किन्तु उनकी संख्या पांच से अधिक न होगी । जब कभी आवश्यक होगा, भारत सरकार के मंत्रिव, और गज्य सरकारों के मुख्य सचिव, सचिव तथा विभागों के अध्यक्षों को सभा की बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जायेगा । यदि बोर्ड आवश्यक समझे तो ऐसे व्यक्तियों का भी निमन्त्रित करेगा, जैसे—व्यापार मण्डल और उद्योग संघ, अखिल भारत व्यापारिक संगठन, प्रावेशिक व्यापार मण्डल तथा औद्योगिक संघ की संस्थाएं, राज्य व्यापार निगम, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड तथा शब्द बोर्ड के अध्यक्ष/सभापति ।

6. बोर्ड अपनी कार्य-प्रणाली आप तैयार करेगा । बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये कार्य को बलाने के लिये मदस्यों में से, बोर्ड समितियों का गठन कर सकता है जिनमें बोर्ड द्वारा बनाये हुये सदस्य भी हो सकते हैं किन्तु उनकी संख्या समिति की एक तिहाई संख्या से अधिक नहीं हो सकती । जहा आवश्यक होगा बोर्ड अध्ययन, मर्यादण आदि करेगा या करवायेगा ।

7. बोर्ड की मदस्यता अवैतनिक होगी । गैर-सरकारी सदस्य, यात्रा तथा दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधायें जो भारत सरकार द्वारा मंजूर की जायेंगी, पाने के पात्र होंगे । सरकारी पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता सामान्य नियम, जो उन्हें लागू होते हैं, के अनुसार दिया जायेगा ।

8. बोर्ड समय समय पर जब आवश्यक होगा, अपनी बैठक करेगा । बोर्ड का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा किन्तु बोर्ड जहा आवश्यक रामबोगा, उन स्थानों में जायेगा तथा ऐसे स्थानों में बैठकें भी करेगा ।

9. समय समय पर बोर्ड अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

श्री० नम्पाप्पा, सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION
(Department of Rehabilitation)
RESOLUTION

New Delhi, the 5th February 1968

SUBJECT.—Constitution of a Board of Rehabilitation.

No. 3(5)/67-RH-V.—In continuation of the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 3(5)/67-RH-V. dated the 30th January, 1968, it has been decided to appoint Shri Kamalnayan Bajaj Member of Parliament, as a Member of the Board of Rehabilitation

V. NANJAPPA, Secy.